



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट-ब्यूरो

Code No. : 92

विषय: मानव अधिकार और कर्तव्य

पाठ्यक्रम

इकाई-1 मानव अधिकार और कर्तव्य: संकल्पना और प्रकार

- मूलभूत अवधारणाएं : व्यक्ति, समूह, राज्य, गैर-राज्य कार्यकर्ता, नागरिक समाज, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, समानता, अधिकार, न्याय, मानव मूल्य: मानवता, करुणा, सद्गुण, मानव गरिमा और मानव के कर्तव्य
- मानव अधिकार, सार्वभौमिक, अन्तर्निहित, अविच्छेद्य अधिकार और नैतिक अधिकार के रूप में, वैश्विक मानव अधिकार बनाम संस्कृतिक सापेक्षतावाद, नैशर्गिकवादी-सकारात्मक बहस
- भारतीय अवधारणाएं राज्य नीति, लोक नीति, दण्ड नीति; न्याय, धर्म
- मानव अधिकारों की विभिन्न पीढ़ियां ।
- उदारवादी परिप्रेक्ष्य: लॉक, रूसो, थॉमस पेन, जे एस मिल, शास्त्रीय उदारतावाद, नवउदारतावाद
- मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य: मार्क्स, ग्राम्सी, रोज़ा लक्जम्बर्ग
- गांधीवादी परिप्रेक्ष्य (रास्किन, थोरू, टाल्सटॉय) : राज्य, शक्ति, स्वराज, अधिकार और कर्तव्य
- दलित परिप्रेक्ष्य फुले, नारायण गुरू, अम्बेडकर
- धार्मिक परिप्रेक्ष्य
- नारीवादी परिप्रेक्ष्य

इकाई-2 मानव अधिकारों का उद्गम और क्रमिक विकास तथा अंतरराष्ट्रीय मानक

- प्राचीन पश्चिमी विचारों में मानव अधिकार
- मध्यकाल में मानव अधिकार, मैग्ना कार्टा
- मानव अधिकारों के आधुनिक आंदोलन, लॉक का दर्शन: नैसर्गिक अधिकारों का सिद्धांत, स्वतंत्रता की अमरीकी घोषणा, अमरीकी अधिकार प्रपत्र (बिल ऑफ राइट्स), फ्रांसिसी क्रांति और स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के लक्ष्य, मार्क्सवादी क्रान्ति, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन, भारत में स्वातंत्र्य आंदोलन ।
- अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारण- मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948)

- नये राज्यों के संविधानों पर मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यू डी एच आर) का प्रभाव ।
- अंतर्राष्ट्रीय मानक: संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित या मानव अधिकार संबंधी 'मूल' अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय : इंटरनेशनल कोवनेन्ट ऑन सिविल एण्ड पॉलिटिकल राइट्स (आई. सी. पी. आर), इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशिएल एण्ड कल्चरल राइट्स (आई सी ई एस सी आर), कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फार्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एगेंस्ट विमन (सी ई डी ए डब्ल्यू), उत्पीड़न के विरुद्ध अभिसमय, बाल अधिकारों पर अभिसमय, प्रवासी कर्मकारों के अधिकारों संबंधी अभिसमय, नस्ली भेदभाव के विरुद्ध अभिसमय (सी आर डी), अशक्त व्यक्तियों के अधिकार संबंधी अभिसमय (सी आर पी डी)।
- मानव अधिकारों की सुरक्षा संबंधी राज्य के दायित्व: "सुरक्षा संबंधी दायित्व" की संकल्पना
- मानव अधिकार संबंधी वियना घोषणा, 1993
- हेलसिंकी घोषणा
- एसियान (एसईएएन घोषणा) ।

इकाई-3 समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, धर्म और संस्कृति – इनके अन्तरसम्बंध

- मानव व्यवहार पर सामाजिक ढांचे का प्रभाव, मानव मूल्यों, मानव अधिकारों एवं कर्तव्यों में सामाजिकरण की भूमिका ।
- विज्ञान और तकनीकी विज्ञान, आधुनिकीकरण, भूमंडलीयकरण और अमानवीकरण ।
- सामाजिक विभाजन: नस्लवादी और जातीय पूर्वाग्रह और भेदभाव, कमजोर तबकों और जातीय अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार ।
- महिलाएं : लिंगभेद, घरेलू हिंसा एवं महिलाओं के प्रति अपराध ।
- बच्चे: बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, बाल मजदूर, गली के बच्चे ।
- सामाजिक ढांचा और सामाजिक समस्यायें : सामाजिक एवं साम्प्रदायिक टकराव एवं सामाजिक सामंजस्य ।
- ग्रामीण गरीबी, बेरोजगारी, बँधुआ मजदूर, दासता के आधुनिक रूप ।
- शहरी गरीबी, झुग्गी-झोपड़ी बस्तियां, मूलभूत नागरिक सेवाओं का अभाव, सेक्स कर्मकार।
- शरणार्थियों के अधिकार, देशी लोगों, वृद्धों, प्रवासी कर्मकार एवं मानवाधिकार उल्लंघन, अशक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अधीन अशक्त व्यक्तियों के मानवाधिकार, विस्थापित व्यक्तियों के अधिकार ।
- मानव अधिकारों की चुनौतियां धार्मिक रूढ़िवादिता, आतंकवाद, विकास की कमी, मानव तस्करी, अंतर्राष्ट्रीय अपराध ।

इकाई-4 राज्य और व्यक्ति की स्वतंत्रता

- विकासशील देशों के विशिष्ट परिप्रेक्ष्य में राज्य की बदलती प्रकृति ।
- लचीला राज्य, हस्तक्षेपीय राज्य, कल्याणकारी राज्य, दमनकारी राज्य ।
- राजनीतिक हुकूमतें और मानव अधिकार ।
- मानव अधिकारों और कर्तव्यों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रभाव ।
- मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति : एक नई वैश्विक व्यवस्था का उदय – तेहरान सम्मेलन (1968) – वियना सम्मेलन (1993) ।
- अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून: 1949 जेनेवा समझौता और 1977 के अतिरिक्त नयाचार- अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सौसाइटी ।
- अंतर्राष्ट्रीय अपराधिक न्यायाधिकरण (रवांडा और पूर्व युगोस्लाविया) और अंतर्राष्ट्रीय अपराधिक न्यायालय (आई सी सी) ।
- अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप: राष्ट्र-राज्य, नागरिकता और संप्रभुता के मुद्दे ।
- आत्म-निर्णय का अधिकार: स्वायत्त आंदोलन, अलगाववादी आंदोलन ।
- जनांदोलन और मानव अधिकार ।

इकाई-5 संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) और विभिन्न एजेन्सियां, अंतः सरकारी (आई जी ओ) और गैर-सरकारी संगठन (आई एन जी ओ)

- यू एन: स्थापना, उद्देश्य और चार्टर प्रावधान
- यू एन के प्रमुख संगठन: जनरल एसेंबली, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद
- सहायक संगठन: ह्यूमन राइट्स काउंसिल (मानव अधिकार परिषद)
- मानव अधिकार सलाहकार परिषद समिति
- विशिष्ट एजेन्सियों की भूमिका: यूनिसेफ, यूनिस्को, आई एल ओ डब्लू एच ओ
- आई एन जी ओ यथा इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट (आई सी जे) एन्नेस्टी इंटरनेशनल (ए आई), ह्यूमन राइट्स वाच, ग्रीनपीस
- पीप्लस यूनिशन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी यू सी एल) पीप्लस यूनिशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (पी यू डी आर) और भारत में अन्य नागरिक और जनतांत्रिक अधिकार संगठन
- यू एन हाई कमीशन फॉर रिफूजी (यू एन एच सी आर)
- यू एन कमीशन ऑन द स्टैटस ऑफ विमन
- यू एन हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स

इकाई-6 संवृद्धि के प्रतिमान और मानव अधिकार

- विकास के प्रतिमान: वृद्धि का दृष्टिकोण, मूलभूत जरूरतों का दृष्टिकोण, संपोषणीय मानव विकास, पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा, 1992, रियो+20, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, एजेन्डा 21, जैव-विविधता अभिसमय 1992
- भूमंडलीकरण और मानवाधिकार: भूमंडलीकरण का गतिशास्त्र, बाजार शक्तियों का उदय, नागरिक समाज का दावा, राज्य का निवर्तन, निजीकरण, उदारीकरण।
- सूचना युग का उदय।
- आर्थिक उत्पादन की रणनीतियां (विकासशील देश) गरीबी उन्मूलन के प्रभाव, रोजगार मद्दे, नियोजित विकास और सामाजिक असमानता
- विश्व व्यापार संगठन : मानवाधिकारों पर प्रभाव – भारत के विशेष संदर्भ में विकासशील देशों पर प्रभाव;
- बौद्धिक संपदा अधिकार : पेटेंट कानून, व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार (ट्रिप्स), व्यापार संबंधी-निवेश के उपाय (ट्रिप्स), व्यापार और सेवाओं संबंधी समान्य करार (गैट्स), कृषि संबंधी समझौता (AOA)
- बहुराष्ट्रीय कंपनियों (TNC) और विकासशील देशों में मानवाधिकार की स्थिति
- विकास का अधिकार : तीसरी दुनिया के सरोकार, कार्यकारी समूह की सिफारिशें, यू.एन.डी.पी. पहल, विकास के अधिकार संबंधी यू एन घोषणा
- भारत में उपेक्षित / वंचित समूहों की स्थिति : गरीब, बेरोजगार और सामाजिक विस्थापन झेल रहे लोग
- कर्मकारों के अधिकार, न्यूनतम वेतन अधिनियम – कार्यान्वयन की समस्याएं, आहार की निश्चितता का अधिकार, स्वास्थ्य शिक्षा

इकाई-7 विकास, अल्पविकास और सामाजिक क्रिया

- विकासशील समाजों में सामाजिक क्रिया की आवश्यकता और सामाजिक क्रिया की विधियां।
- भूमि, जल और वन संबंधी मुद्दे, भारत के विशेष संदर्भ में।
- सामाजिक आंदोलन : राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सुधार।
- महिला, बाल, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और जनजाति संबंधी राष्ट्रीय आयोग।
- पिछड़ा वर्ग, दलित और महिला आंदोलन।
- खेतिहर और किसान आंदोलन।
- स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार।
- संपोषणीय विकास का सिद्धांत।
- पारस्थितिकी और पर्यावरण आंदोलन।
- नागरिक समाज और एन. जी. ओ., भारत के एन. जी. ओ.।

इकाई-8 मानव अधिकार और भारतीय संविधान

- भारतीय सभ्यता : परिवर्तन और निरंतरता
- भारतीय संविधान : स्वाधीनता आंदोलन
- भारतीय संविधान : समाजशास्त्रीय आधार
- राज्य की भूमिका की संवैधानिक समझ
- स्वतंत्रता की संवैधानिक समझ : मौलिक अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मानक
- न्याय की संवैधानिक समझ : राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त और अंतर्राष्ट्रीय मानक
- जनहित मुकदमें (पी आई एल), भारतीय न्यायापालिका और मानव अधिकार
- न्यायिक निर्वचन : प्रमुख फैसले
- संविधान संशोधन
- मूल कर्तव्य

इकाई-9 संवैधानिक शासन

- कानून का शासन, सुशासन
- संवैधानिक संगठन : अंतर एवं अन्तर्संबंध / विवाद और सहयोग ।
- मौलिक अधिकार और दमनकारी कानून : निरोधक नजरबंदी और आंतक निरोधक अधिनियम, सशस्त्र बल (विष्टिय शक्तियां) अधिनियम ।
- राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा : सामाजिक अनुभव
- आपराधिक न्याय व्यवस्था : भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक दंड संहिता (CRPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विशेष संदर्भ में अपराध, दंड और मानवाधिकार ।
- आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार : राज्य के नीति निदेशन सिद्धांत : प्रभावकारिता और प्रवर्तन के प्रश्न, मौलिक अधिकारों से उनका संबंध ।
- दुर्बल वर्गों के लिए विधायन : प्रवर्तन के प्रश्न
- विधि प्रवर्तनकारी एजेन्सियां : पुलिस, मिलेटरी और पैरामिलेटरी बल – उभरते अनुभव
- मानव अधिकार प्रवर्तन : मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993, मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार न्यायालय
- मानवाधिकार शिक्षा : समस्याएं एवं भविष्य

इकाई-10 मानव अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय क्रियान्वयन

- मूल मानव अधिकार समझौतों के अधीन संधि निकाय : सामान्य सिंहावलोकन
- “वैश्विक आवधिक समीक्षा” और “विशेष प्रक्रियाएं”
- मानव अधिकार समिति
- आर्थिक और सामाजिक अधिकार समिति (CESCR)
- महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति की समिति (सी ई डी ए डब्ल्यू)
- मानव अधिकार का यूरोपीय न्यायालय (ECHR)
- मानव अधिकार संबंधी अंतः अमरीकी आयोग
- मानव अधिकार संबंधी अंतः अमरीकी न्यायालय
- मानव और लोगों के अधिकारों संबंधी अफ्रीकी आयोग
- अफ्रीकी न्यायिक न्यायालय और मानव अधिकार, 2008